

## खबर संक्षेप

क्षतिग्रस्त ध्वजों को बदल दिया जाना चाहिये



मण्डला। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे नगर को राम ध्वजों से सजाया गया है। बीते समय के साथ-साथ ये ध्वज क्षतिग्रस्त हो गये हैं। इन क्षतिग्रस्त ध्वजों का यूँ लहराते रहना शोभा नहीं दे रहा सभी सनातनी यह चाहते हैं कि इन ध्वजों को बदल दिया जाये और इनके स्थान पर नये ध्वज लगा दिये जायें ताकि एक ओर जहाँ लोगों की धार्मिक भावनायें प्रभावित न हों वहीं दूसरी ओर नगर की सुन्दरता भी कायम रह सके।

## एसबीआई ने विद्यार्थियों को दिये लैपटॉप



मण्डला। सामाजिक सेवा बैंकिंग के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मण्डला बालाघाट और सिवनी जिले के आदिवासी जनजाति के पांच मेरिटोरियस स्टूडेंट को लैपटॉप का वितरण किया है। यहाँ पर राकेश कुमार उइके, लवकेश तांडे, देविका पांडे, अमोल निकोसे, अनुष्का वालके को लैपटॉप दिया गया इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक अर्जुनसिंह बिष्ट ने कहा की भारतीय स्टेट बैंक सामाजिक सहभागिता के लिए इस तरह के सामाजिक सेवा कार्य करती रहती है इसी तारतम्य में सोमवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

## छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं करने पर प्राचार्य निलंबित

मण्डला। पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने, छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं करने पर कामिश्नर अभय वर्मा द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिंडरई की प्रभारी प्राचार्य फूलवती परस्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रभारी प्राचार्य फूलवती परस्ते द्वारा विद्यालय के 877 विद्यार्थियों में से केवल 554 बच्चों का ही प्रोफाइल पंजीयन किया गया है तथा किसी भी बच्चे की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की गई है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मंडला नियत किया गया है।

## निर्देश

## भ्रमण करते हुए योजनाओं में प्रगति लाएँ-डॉ. सिडाना

## आदर्श ग्राम चयन की प्रक्रिया शीघ्र हो

## \* योजनाओं का फीडबैक भी प्राप्त करें।

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

समय-सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी आवंटित क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए विभागीय योजनाओं में प्रगति लाएँ। भ्रमण के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक फीडबैक प्राप्त करें तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करें। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट, अपर कलेक्टर राजेन्द्र



## थानों एवं चौकियों में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान

## नए कानूनों के बारे में दे रहे जानकारी

## \* पुलिस अधीक्षक ने लोगों को विस्तार से समझाया।

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

कल 01.07.2024 से नये कानूनों की शुरुआत हुई जिसको लेकर समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नवीन अपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। तीनों नवीन कानून-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को सरकार के द्वारा आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ित की समस्याओं को केंद्र में रखकर अपराधियों के लिए कड़ी सजा आदि का प्रावधान किया गया है। कहीं पर भी घटना होने पर किसी भी थाना पर FIR की सुविधा तथा घर बैठे ही E-FIR का भी प्रावधान है। नये कानून में डिजिटल व फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को भी बढ़ाया गया है एवं प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। जैसे:- कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्जशीट पेश



करना है और केस की अपडेट पीड़ित को कितनी समय सीमा में दी जाएगी। गवाह व पीड़ित आदि के बयान की वीडियो प्राप्ति करना तथा बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने की भी प्रक्रिया है। पुलिस टीम ने आमजन को नए व पुराने कानूनों के तुलनात्मक चार्ट और प्रावधानों को पीपीटी व पोस्टर आदि के माध्यम से समझाया। इसके साथ ही आमजन को भी इसकी जानकारी रहे इसे ध्यान में रखते हुए जिला मण्डला के सभी थानों में भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा तुलनात्मक विवरण के पोस्टर लगाये गये ताकि थाने पर आने वाले किसी भी फरियादी एवं आमजन को नवीन अपराधिक कानून की विभिन्न धाराओं व प्रावधानों के

साथ अपराधिक विधिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी रहे।

## महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान

नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। प्रस्तावित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पहला अध्याय अब महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित सजा के प्रावधानों से संबंधित है। इन प्रावधानों के अनुसार जहाँ बच्चों से अपराध करवाना व उन्हें अपराधिक कृत्य में शामिल करना दंडनीय अपराध होगा वहीं नाबालिग बच्चों की खरीद-फरोख्त जघन्य अपराधों में शामिल की जाएगी। नाबालिग से

गैररप किए जाने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। नए कानूनों के अनुसार पीड़ित का अभिभावक को उपस्थिति में ही बयान दर्ज किया जा सकेगा। इसी प्रकार नए कानूनों में महिला अपराधों के संबंध में अत्यंत सख्ती बरती गई है। इसके तहत महिला से गैररप में 20 साल की सजा और आजीवन कारावास, यौन संबंध के लिए झूठे वादे करना या पहचान छिपाना भी अब अपराध होगा। साथ ही पीड़ित के घर पर महिला अधिकारी की मौजूदगी में ही बयान दर्ज करने का भी प्रावधान है। इस प्रकार नए कानून में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध घटित करने वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कड़ी सजा के प्रावधान हैं।

## नए कानूनों से होने वाले लाभ

ई-एफआईआर के मामले में फरियादी को तीन दिन के भीतर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करने होंगे। नए बदलावों के तहत जीरो एफआईआर को कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया है। फरियादी को एफआईआर, बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है। यानी वे पेनड्राइव में अपने बयान की कॉपी ले सकेंगे। इस प्रकार नए कानूनों में आमजन को बहुत सारे लाभ प्रदान किए गए हैं।

## नए कानूनों में खास

अदालतों में पेश और स्वीकार्य साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, मेल, उपकरणों के मैजैस को शामिल किया गया है। केस डायरी, एफआईआर, आरोप पत्र और फैसेले सहित सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भी न्यायालयों में पेश हो सकेगी। अब 60 दिन के भीतर आरोप तय होंगे और मुकदमा समाप्त होने के 45 दिन में निर्णय देना होगा। वहीं सिविल सेवकों के खिलाफ मामलों में 120 दिन में निर्णय अनिवार्य होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत मामलों की तय समय में जांच, सुनवाई और बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला देने का प्रावधान है। इसी प्रकार छोटे और कम गंभीर मामलों के लिए समरी ट्रायल अनिवार्य होगा। नए कानूनों में पहली बार अपराध पर हिरासत अवधि कम रखी जाने व एक तिहाई सजा पूरी करने पर जमानत का प्रावधान है। साथ ही किसी भी शिकायतकर्ता को 90 दिन में जांच रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा और रिपॉर्टर व्यक्तित्व की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी।

## नए कानूनों से होने वाले लाभ

ई-एफआईआर के मामले में फरियादी को तीन दिन के भीतर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करने होंगे। नए बदलावों के तहत जीरो एफआईआर को कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया है। फरियादी को एफआईआर, बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है। यानी वे पेनड्राइव में अपने बयान की कॉपी ले सकेंगे। इस प्रकार नए कानूनों में आमजन को बहुत सारे लाभ प्रदान किए गए हैं।

## नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर कांग्रेसियों ने फूँका पुतला



हरिभूमि न्यूज | मण्डला

मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें अस्तित्वहीन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता एवं नर्सिंग कॉलेज से संबंधित छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने की घटना विस्तृत रूप से उजागर हुई है जिसमें मध्यप्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उक्त नर्सिंग घोटाले में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यकाल की घटनाएं उजागर हुई हैं जिसके लिए मंत्री श्री सारंग सीधे-सीधे जिम्मेदार है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री विश्वास सारंग आज भी अपने पद पर काबिज है।

उपरोक्त नर्सिंग कॉलेज घोटाला छात्र-छात्राओं के भविष्य के अंधकारमय करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुख्य अवर सचिव मोहम्मद सुलेमान, तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत बरबडे सहित कई अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों की संलिप्तता उजागर हो रही है। ऐसी

स्थिति में प्रदेश में छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों सहित आम जनता में भारी रोष व्याप्त है।

महामहिम राज्यपाल से प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले जैसे कलंक की सम्पूर्ण जांच कराकर कार्यवाही की जाने एवं जांच पूर्ण होने के पूर्ण प्रथम दृष्टा अपराध में संलिप्त प्रतीत हो रहे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान एवं निशांत बरबडे को तत्काल निलंबित कर जांच कार्यवाही कराई जाने एवं मंत्री विश्वास सारंग को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने की मांग जिला कांग्रेस कमेटी मण्डला ने अपने ज्ञान के माध्यम से की।

इस दौरान पूर्व विधायक डॉ अशोक मसंकोले, जिला कांग्रेस अध्यक्ष एड. राकेश तिवारी, मुकेश कछवाहा, बब्बी राय, योगेश उपाध्याय, इंद्रजीत भंडारी, कमलेश तिलगाम, नूरेएन मंसूरी, श्रीकांत कछवाहा, रजनीश रंजन उसरारे, इकबाल खान, सौरभ साहू, मीडिया प्रभारी विवेक दुबे शामिल रहे।



## कानून की नई किताबों को पुलिस ने किया प्रदर्शित

हरिभूमि न्यूज | मण्डला | मुआबिधिया

बिछिया पुलिस थाना परिसर में सोमवार को नया भारत-नया विधान के अंतर्गत 01 जुलाई 2024 से लागू हुआ नए कानून और बदली हुई धाराओं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आदि के बारे में आम नागरिकों को अवगत कराने और जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। उपस्थित नागरिकों को नए अधिनियम, ई एफआईआर, बदली हुई धाराएं, साक्ष्य अधिनियम



में हुए बदलाव, नए सजा के प्रावधान, गवाहों के वीडियो रिकॉर्डिंग संबंधित कानून आदि के बारे में अवगत कराया। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस

आसिफ खान ने नए कानून और बदली हुई धाराओं की जानकारी देते हुए नये कानून के माध्यम से नागरिकों की सुरक्षा के लिए गए प्रावधान से अवगत कराया। बच्चों

से जुड़ी धाराएं और कानून की विस्तृत जानकारी उदाहरण के माध्यम से समझाई गई।

बिछिया टी.आई. धर्मेंद्र सिंह धुवें ने कानून की नई किताबों को प्रदर्शित कर नागरिकों को और नए कानून व धाराओं से जुड़ी जानकारी दी। कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार, समाजसेवी, पुलिस सहयोगी दल के सदस्य, जनपद सदस्य, पार्षदाणा एवं नागरिक उपस्थित थे।

## घुघरी में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

हरिभूमि न्यूज | मण्डला/घुघरी

कल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घुघरी के समस्त कांग्रेस जन जनता की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घुघरी के माध्यम से 13 बिंदुओं का अविलंब निराकरण कराने हेतु ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है जो निम्नानुसार है- नर्सिंग घोटाला की उच्च स्तरीय जांच की जाए एवं दोसिये के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शीघ्र किया जाए। विधान सभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये एवं धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये की घोषणा की गई थी, शीघ्र लागू किया जाए। विधान सभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गैस की कीमत 450 की घोषणा की गई थी शीघ्र लागू किया जाए। विधान सभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाडली बहना योजना अंतर्गत महिलाओं को 3000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई थी शीघ्र दिया जाए। तहसील मुख्यालय घुघरी में व्यवहार न्यायालय की स्थापना किया जाए। तहसील मुख्यालय घुघरी में महाविद्यालय की स्थापना किया जाए। विकासखंड घुघरी के बालक एवं बालिका छात्रावासों में सीट वृद्धि किया जाए। तहसील मुख्यालय घुघरी में विश्राम गुह की



स्थापना किया जाए। विकासखंड घुघरी में विधुत विभाग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जावे। विकासखंड घुघरी अंतर्गत ग्रामों में स्वीकृत नल जल योजना में ठेकेदार द्वारा 100 प्रतिशत धरों में नल जल योजना का कनेक्शन नहीं किया गया है जिसे पूरा किया जाए एवं घटिया किस्म के पाइप लाईन डालने के कारण जगह-जगह लीकेज होने के कारण पूर्ण किए गए ग्रामों में योजना संचालित नहीं हो पा रही है जिसकी जांच किया जाय। बस स्टैंड घुघरी का फर्शिकरण कार्य हो चुका है सब्जी व्यापारियों को दुकान लगाने हेतु उचित स्थान दिया जाए ताकि यात्री एवं बस स्टैंड में रुक सके। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुघरी में महिला डॉक्टर की अर्बिलंब नियुक्ति की जाए। पदमी रामनगर

घुघरी सलवाह मार्ग का निर्माण जारी है परंतु घुघरी में सड़क किनारे अतिक्रमण होने के कारण पूर्ण नहीं हो पा रहा है शीघ्र अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही करते हुए निर्माण कार्य जारी कराया जाए। इस अवसर पर अरविंद कुमार कुशराम अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घुघरी, नेतारम साहू विधायक प्रतिनिधि घुघरी एवम जिला महामंत्री, श्रीमती गीता मरावी जिला पंचायत सदस्य, अमर लाल मांडवे सेवादल अध्यक्ष, संजु पटेल मंडल अध्यक्ष, अरविंद झरिया ब्लॉक प्रवक्ता, मेवा धुवें, अशोक अहिरवार सेक्टर अध्यक्ष, गणेश परते, सोहन उदे, पंकज झरिया, अंकित दुबे सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

## कार्यालय नगर परिषद निवास जिला मण्डला (म.प्र.)

क्र/नोपरि/0/2024/199

// निविदा आमंत्रण-सूचना//

निवास, दिनांक 28/06/2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद निवास द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 (15 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक) के लिये दैनिक, साप्ताहिक मंडई घुघरी एवं काली हाउस की निरामी किया जा रहा है। अतः इच्छुक व्यक्ति दिनांक 08/07/2024 तक कार्यालयीन समय में अमानत राशि जमा कर नीलामी तिथि को बोली में भाग ले सकते हैं।

क्र.	नीलामी तिथि	नीलामी मज	समय	शासकीय बोली	अमानत राशि
1	दैनिक, साप्ताहिक बाजार एवं मंडई-गुदरीबाजार नीलामी	09/07/2024 दिन मंगलवार	दोपहर 12:00 बजे से नगर परिषद सम्भाकक्ष में।	1016000/-	25000/-
2	कांजी हाउस नीलामी	09/07/2024 दिन मंगलवार	दोपहर 12:00 बजे से नगर परिषद सम्भाकक्ष में।	35500/-	5000/-

टीप- 1-अमानत राशि जमा उपररत ही नीलामी में भाग ले सकते हैं। 2-नीलामी में भाग लेने वाले ठेकेदार को अपने नाम से जमा पित्त एवं परिवार के सदस्यों के नाम से विकसय के समस्त करों का मुकतान कर प्रमाण पत्र राजस्व प्रमारी से प्राप्त कर अमानत राशि जमा करेगे।

श्रीमति हेमलता परस्ते अध्यक्ष नगर परिषद निवास श्री बसंत चौधरी उपाध्यक्ष नगर परिषद निवास श्रीमति राजकुमारी सिंगारेरे सभापति राजस्व नगर परिषद निवास श्री गजानन नाफडे मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद निवास

## खबर संक्षेप

## सिहोरा में अन्य बैक शाखाएं खोलने की उठ रही मांग

सिहोरा/बोहानी। इस समय सिहोरा क्षेत्र के लगातार हो रहे विकास के साथ साथ केन्द्र से लेकर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ भी लोगों को बैंकों के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इतना ही नहीं इस क्षेत्र में के लोग जहां मूलरूप से कृषि से जुड़े हुए हैं, वहीं यहां पर रेल्वे स्टेशन, पुलिस चौकी, विद्युत मंडल कार्यालय, टेलीफोन आफिस, शासकीय एवं निजी चिकित्सालय, शासकीय महाविद्यालय, शासकीय व निजी स्कूल, गुड मंडी, अनाज मंडी सहित अन्य एजेन्सी संचालित हो रहे हैं जिसके चलते लोगों का अधिकांश कार्य बैंकों के माध्यम से ही चलता है, मगर सिहोरा क्षेत्र में मात्र एक ही बैक शाखा होने के कारण जहां लोगों को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करने मजबूर होना पड़ रहा है, वहीं वह पैसों के लेन देन में भी काफी दिक्कतों से घिरे होने के कारण क्षेत्र के लोगों द्वारा अन्य निजी बैंकों के साथ साथ शासकीय बैंकों की शाखाएं खोलने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर सिहोरा क्षेत्र के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से सेटल बैक आफ इंडिया, यूनियन बैक ऑफ इंडिया के आलवा रिजर्व बैक को भी एक आवेदन देते हुए यहां अन्य बैंकों की शाखाएं खोलने की मांग की गई है, क्योंकि शायद ही क्षेत्र में कोई ऐसा कर्षा होगा जहां पर लोगों द्वारा संबंधित बैंकों के अधिकारियों को सामूहिक रूप से आवेदन देते हुए बैक शाखाएं खोलने की जागरूकता दिखाई गई है। वहीं दूसरी ओर लोगों द्वारा जिला कलेक्टर से भी मांग की गई है कि वह सिहोरा में अन्य बैंकों की शाखा खोलवाने हेतु प्रयास करे जिससे लोगों को बैंकों के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।

## अंडा दुकानों से बिगड़ रहा माहौल

सालीचौका। इस समय जिस प्रकार से शराबखोरी करने वाले लोगों से आमजन को परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर होते हुए देखा जा रहा है, उसके चलते नगर की कानून व्यवस्था पूर्णरूप से पटरी पर उतरते हुए देखी जा रही है, इस सब का प्रमुख कारण मात्र एक ही देखा जा रहा है कि नगर के अंदर संचालित होने वाली पान दुकानों के चलते एक ओर नगर का वातावरण प्रदूषित होने से नहीं बच पा रहा है, वहीं दूसरी ओर इन अंडा दुकानों पर शाम होते हुए जिस प्रकार से शराबखोरी करने वाले लोगों का जमावाड़ा लग जाता है उसके चलते आम लोगों मुख्य मार्गों से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नगर में जहां तहां लगी हुई इन अंडा दुकानों के चलते स्थिति इस प्रकार से देखी जा रही है कि शराब के नशे में मस्त लोगों द्वारा जिस प्रकार से अपराधों का उपयोग किया जाता है उसके चलते यहां पर रहवास करने वाले लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है।

## खुले पड़े शौचालयों की संचाई को नगर अंदाज किया जाना पड़ रहा है मारी सालीचौका।

देश को स्वच्छ व स्वास्थ्य बनाने की सोच के चलते सरकार द्वारा शुरू की गई स्वच्छता की मुहिम के चलते जिस प्रकार से लगभग चार वर्ष पूर्व जिस प्रकार से जिले से लेकर ब्लाक स्तर पर बैठे हुए अधिकारियों द्वारा अपनी वाही वाही लूटने के लिए जिले को बाह शौच घोषित मुक्त कराये जाने की जो रामलीला की गई थी, उसको लेकर स्थानीय अखबारों द्वारा लगातार इस बात को उजागर किया जा रहा था कि जब लोगों के घरों में अभी तक शौचालयों का निर्माण हुआ ही नहीं है तो फिर आखिर में जिला बाह्यशौच मुक्त घोषित कर कैसे दिया? मगर इस बात को लेकर न तो उस समय जिले के नेताओं द्वारा ध्यान दिया गया और न ही विपक्ष में बैठी हुई राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिसका परिणाम यह हुआ कि जिला स्तर पर बैठे हुए अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार से अपनी वाही वाही लूटने के लिए संपूर्ण जिले को इस प्रकार से लगभग चार वर्ष पूर्व प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा बाह्यशौच मुक्त घोषित कराते हुए सम्मान पाया गया था, वह सिर्फ चर्चा का विषय ही नहीं बल्कि उस समय विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों की उदासीनता को भी उजागर करते हुए जान पड़ रहा था?

## वृक्षारोपण के नाम पर किये जा रहे करोड़ों खर्च फिर भी दिखाई नहीं दे रही है हरियाली



हरिभूमि न्यूज/गाइरवारा।

आये दिन देखा जाता है कि लोगों द्वारा सुर्खियों में छाने की होड़ के चलते जहां तहां वृक्षा रोपण इस प्रकार से किया जाता है कि शायद वह पर्यावरण को सुधारने में अहित भूमिका निभाने से नहीं चूकेगे? मगर वहीं दूसरी ओर यदि इस संचाई पर गौर किया जावे तो उनकी यह मुहिम दूसरे दिन अखबारों में फोटो प्रकाशित होने तक ही सीमित रहने की स्थिति के आलवा और कुछ साबित होने से नहीं चूक पाती है? शासन द्वारा हर वर्ष पर्यावरण सुधार को लेकर वृक्षारोपण के नाम पर खर्च की जाने वाले इस सरकारी राशि की संचाई पर गौर किया जावे तो पूर्व के समय में अनेक जगहों पर नेताओं से लेकर अधिकारियों द्वारा रोपे गये वृक्षों का क्या हाल है यह बात शायद ही किसी से छिपी नहीं है? क्योंकि वृक्षारोपण के उपरांत शायद ही कभी किसी नेता, अधिकारी द्वारा रोपे गये वृक्ष की खबर लेते हुए देखा गया हो? इस संबंध में बताया जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत क्षेत्रवासियों की उम्मीद थी कि शायद इस योजना के तहत लगभग पांच सात वर्ष पूर्व से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में लाखों की राशि खर्च करते हुये पैदा रोपे गये थे। यदि इन पौधों का रोपण निष्ठा के साथ किया गया होता तो वह सात साल में पेड़ बने चुके होते, मगर संचाई यह है कि उनके दर्शन दुर्लभ होने से नहीं चूक रहे हैं? वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की संचाई पर नजर डाली जावे तो आलम यह है कि लगातार एक पेड़ तो गायब ही है साथ ही उनके लिए बने प्लेट फार्म भी लगभग गायब होते जा रहे हैं और पौधा रोपण के नाम पर पंचायतों के माध्यम से खर्च की गई करोड़ों की राशि से जमीन पर हरियाली की जगह पंचायत के जनप्रतिनिधियों से लेकर कर्मचारियों के चेहरों

पर जरूर दिखाई देने से नहीं चूक पा रही है? संचाई पर नजर डाली जावे तो क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायतों में वर्तमान समय तक ब्युजिकल 10 प्रतिशत भी पेड़ सुरक्षित नहीं है। अधिकतर ग्राम पंचायतों का हाल यह है कि लगभग सारे पेड़ सूख चुके हैं और उनके लिए बनाए गए प्लेट फार्म टूटकर बिखरते हुये दिखाई देने से नहीं चूक पा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ वर्ष पहले क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को काम देने और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से शासन की राशि खर्च करते हुये बड़ी संख्या में पेड़ लगाए गए थे जिसके लिए करोड़ों रुपये का बजट खर्च किया गया था। वहीं इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण, वृक्षों की सुरक्षा एवं संचाई पर लगभग लाखों रुपये की राशि खर्च की गई थी। लेकिन इस प्रकार से खर्च की गई राशि का शायद ही कहीं दिखाई दे रहा हो? यही हाल पंचायतों में भी देखा जा रहा है जहां पर बीते हुये बारिश के दौरान बड़े उत्साह के साथ किये गये वृक्षारोपण के चलते किसानों के खेतों में मेड़ो पर पंचायतों द्वारा वृक्षारोपण करते हुये पंचायतों के बिल बाऊचर तो हरयाते हुये देखे जा रहे हैं। मगर मौके पर पेड़ शायद ही कहीं नजर आ रहे हो? बताया जाता है कि संपूर्ण जिले में बीते हुये बारिश के सीजन पर हरियाली योजना के अंतर्गत क्षेत्र की लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पौधे लगाने के लिए राशि उपलब्ध कराई गई थी जिसमें क्षेत्र की सभी पंचायतों में वृक्षा रोपण किया गया था, जो मुख्य सड़कों के साथ साथ ग्रामों में किसानों की मेड़ो पर भी पंचायतों द्वारा वृक्षारोपण के नाम पर राशि खर्च की गई थी। मगर सवाल यह पैदा हो रहा है कि लाखों की राशि खर्च करते हुये पंचायतों द्वारा रोपे गये पौधा कहा गायब हो गये किसी को पता ही नहीं है? इस प्रकार से सही मायने में देखा जावे तो वह वृक्षारोपण कार्यक्रम मात्र कागजों

तक ही सीमित होकर सिर्फ शासकीय राशि को बर्बाद करने का खेल ही साबित होते हुए जान पड़ रहा है? कुछ वर्ष पहले शासन के आदेश के चलते सभी पंचायतों को अपने अपने ग्रामों में वृक्षारोपण करने के आदेश जारी किये गये हैं जिसके चलते अनेक पंचायतों द्वारा अपने अपने गांवों में वृक्षारोपण करते हुए सोशल मिडिया या फिर अन्य साधनों के तहत अधिकारियों ने तक पौधा रोपण करने की फोटो पहुंचाने में देर नहीं की गई थी जिसके चलते इस प्रकार से वृक्षारोपण कार्य तो हो चुका है और जिन पंचायतों में वृक्षारोपण हुआ है वहां पर एक पेड़ पर इतने लोग बैठकर फोटो निकलवाते हुए दिखाई दे रहे गये थे कि पेड़ को सुरक्षित रहने की कल्पना ही मुश्किल होते हुये जान पड़ने से नहीं चूक रही थी? जबकि संचाई पर गौर किया जावे तो जिन पंचायतों में वृक्षारोपण हुआ है यदि उन पंचायतों के सरपंचों से पूछा जावे की आखिर में उनके द्वारा कौन कौन से पेड़ रोपे गये हैं तो उन्हें भी उनका पता ही नहीं होगा कि उनके द्वारा रोपे गये पेड़ का नाम क्या है और रोपे गये पौधों की स्थिति इस समय किस प्रकार की है? इस प्रकार की संचाई के चलते जहां शासन के आदेश पर हर वर्ष पंचायतों में वृक्षारोपण के नाम पर शासकीय राशि की बर्बादी होते हुए आसानी से देखा जा रही है? वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि किस प्रकार से शासन द्वारा गांवों व शहरों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण करने की मुहिम चलाई जा रही है जिसके चलते ग्राम पंचायतों में शासन की राशि की होली खेलते हुये कागजों में खूब वृक्षारोपण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मगर आज यदि मौके पर जाकर देखा जावे तो शायद ही किसी पंचायत में चंद माह पूर्व रोपे गये पौधे दर्शन हो पाये यह मुश्किल बात है? जहां शासन द्वारा नये वृक्षों को रोपने के लिए लगातार मुहिम चलाते

हुए शासकीय राशि खर्च कर रही है। मगर जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए कोताही बरती जा रही है जिसका उदाहरण आये दिन पेड़ों पर जिस प्रकार से कुल्हाड़ी चलते हुए देखी जाती है उससे शासन द्वारा वृक्षा रोपण के नाम पर चलाई जाने वाली मुहिम पर अपने आप ही प्रश्न चिन्ह लगते हुए दिखाई देने से नहीं चूक रहा है? क्योंकि शहर की शासकीय भूमि पर जहां तहां लगे हुए हरे वृक्षों पर दना दान कुल्हाड़ी चलते हुए देखी जा रही है। कुछ इसी प्रकार का हाल ग्रामीण क्षेत्रों में भी आसानी से देखने मिल रहा है, जिसको लेकर लोग यह बात कहने से नहीं चूके कि एक ओर शासन पंचायतों में पर्यावरण सुधारने के लिए हरियाली फैला रहा है। वहीं दूसरी ओर जहां हरे भरे वृक्ष खड़े हुए हैं उन पर कुल्हाड़ी चलवा रहा है? काबिल गौर है कि कुछ इसी प्रकार से लगभग सात वर्ष पहले ग्राम पंचायतों द्वारा रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को काम मुहैया कराने व विकास के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की गई थी जिसके चलते हर वर्ष पंचायतों में शासकीय राशि खर्च करते हुए सैकड़ों पेड़ लगवाये गये थे वह पांच साल बाद भी नजर नहीं आ रहे हैं जिसके चलते यह योजना मात्र कागजों तक ही सिमट कर रह गई है और क्षेत्र के अनेक ग्राम पंचायतों के बीते हुए पंचवर्षीय कार्यकाल में सरपंच, सचिव व अधिकारियों की इस घोर अनियमितता के चलते क्षेत्रवासियों का हरित क्रांति का सपना अधूरा रह गया है। इसी का परिणाम है जिसके चलते देखा गया था कि गांव गांव वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू होते ही क्षेत्र के नेताओं से लेकर अधिकारियों द्वारा एक पेड़ के साथ साथ चार चार लोगों की सफेदी मारते हुए अखबारों में फोटो दिखाई दे रही थी मगर उनके द्वारा रोपे गये पौधा कहा गायब हो गये इसकी खोजकर पाना मुश्किल ही जान पड़ रहा है?

## शहर में अनेक जगहों पर खाली पड़े हुए भूखंडों की गंदगी से परेशानी, प्लाटों की पड़ताल नहीं करा रहा प्रशासन

हरिभूमि न्यूज/ गाइरवारा। अचल संपत्ति सहेजने की जल्द बाजी में लोगों ने शहर में ढेरों प्लाट तो खरीद लिए हैं पर वर्षों से इन प्लाटों पर उनके द्वारा मकान न बनाने की स्थिति में ये खाली भूखंड शहरवासियों के परेशानियों का कारण बनते जा रहे हैं। अनेक वाडों, कालोनियों के निवासियों ने बताया कि उनके रहवासी क्षेत्र में रिक्त प्लाटों में गंदगी के साथ साथ गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे मच्छरों के पनपने का सिलसिला थम नहीं रहा है और ये खाली भूखंड आवागार जानवरों का अड्डा बनकर रह गए हैं। विदित हुआ है कि नगर के कई वाडों में खाली प्लाटों की खोज खबर उनके मालिक भी नहीं ले रहे हैं, जिससे लोग इन रिक्त प्लाटों का उपयोग कचराघर की तरह कर रहे हैं और नगर के अधिकतर खाली भूखंड झाड़ झकाड़, कांच के टुकड़ों, प्लास्टिक की समस्या से हलका बन गए हैं और वर्षों से बारिश के दिनों के दौरान होने वाला पानी भरने से विशाल गड्ढे में तब्दील होते जा रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि मकान बनाने प्लाट खरीदना बुरी बात नहीं है किन्तु लम्बी अवधि तक इन उपयोग न करना जनहित



की अनदेखी करना चिंता जनक है, जिसके चलते शहर में सर्वत्र पड़े खाली प्लाटों पर जो भीषण गंदगी प्याप है उससे वाडों के निवासी, राहगीर, स्कूली बच्चों तो परेशान हो ही रहे हैं, साथ ही नगर का रूप रंग भी बिगड़ रहा है। इस तरह खाली प्लाटों की समस्या से हलका बन लोंगो के अनुसार हालत यह है कि खाली भूखंडों के मालिकों ने अपने रिक्त प्लाटों की कीमत बढ़ने की आस में उन्हें उपेक्षित छोड़ दिया जाता है और स्वयं के प्लाटों की साफ सफाई करने से मुंह मोड़ लिया, इसके अलावा सार्वजनिक

न होने की स्थिति में नपा. के सफाई कर्मियों ने इन प्लाटों की नियमित सफाई करने से किनारा कर लिया, ऐसी स्थिति में शहर के अनेक वाडों व कालोनियों में खाली पड़े हुए प्लाट आमजनो की मुसीबत का सबब बन गए। वहीं दूसरी ओर के वाडों व कालोनियों के निवासियों ने बताया कि रिक्त पड़े हुये इन प्लाटों की शोचनीय दशा के बारे में आवाज उठाने के बाद भी सम्बंधित प्रशासन ने खाली भूखंडों के मालिकों को अपने प्लाट सुरक्षित करने सचेत नहीं किया और न ही प्रशासन ने कभी यह पड़ताल करायी कि शहर में कितने खाली प्लाट पड़े हैं और उन पर किन कारणों, परिस्थितियों के चलने मकान नहीं बन रहे हैं? और किस अधिकार के तहत खाली भूखंडों के मालिक वाडों, कालोनियों में गंदगी फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, शहरवासियों ने प्रशासन से गुहार लगायी है कि शहर में खाली भूखंडों के मालिकों को वह अगाह करने की पहल करें कि वे अपने गंदगी से युक्त हो रहे प्लाटों की रखवाली करें तथा उनके खाली प्लाट माहौल को प्रदूषित करने का सबब न बनें।

## कल से लागू हुये नये कानूनों के संबंध में पुलिस द्वारा बैठक



हरिभूमि न्यूज/गाइरवारा।

नागरिकों को शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने हेतु तीन नए कानून (भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), कल एक जुलाई 2024 से लागू हो गये हैं। इन नये कानूनों से आमजनों में जागरूकता हेतु बीते हुये सोमवार को अनुविभागीय अधिकारी कलावती व्यारे, उप पुलिस अधीक्षक रत्नेश मिश्रा तथा नगर त्रीक्षक उमेश तिवारी, तहसीलदार नेताम सहित वन अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक का आयोजन करते हुये नये कानूनों की जानकारी से अवगत करायाम गया। उल्लेखनीय है कि देश के

कानून में कुछ बदलाव किए हैं, जो 1 जुलाई को तीन नए कानून गृह मंत्रालय लागू कर रहा है। भारत सरकार द्वारा जो नए कानून जारी किये जा रहे हैं वह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं, जो कि औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन नए कानूनों का उद्देश्य देश के नागरिकों को त्वरित न्याय देना है। साथ ही न्यायिक और अदालत प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना है। एक जुलाई से लागू हुए तीन नए कानूनों के प्रति जागरूकता हेतु आयोजित की गई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि देश में लागू हुए तीन नए कानून (भारतीय

न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) जो कानून लागू हुये हैं अब उन्ही के आधार पर संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया संचालित होगी। वहीं बदलते अपराधिक स्वरूप को देखते हुए नवीन परिभाषाओं एवं विवेचना में तकनीक का प्रयोग। नए कानून का उद्देश्य आमजनों को त्वरित न्याय देना है। जीरो एफआईआर - देश के किसी भी थाने पर दर्ज कराई जा सकेगी। वहीं नये कानून के तहत आम व्यक्ति अब ऑनलाइन भी करा सकते हैं शिकायत दर्ज। अनुसंधान प्रक्रिया एवं साक्ष्य अधिलेखन में डिजिटल प्रणाली के प्रयोग को अपनाया गया है। जैसे - जपती की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो ग्राफी। वहीं को

विवेचना की प्रगति से अवगत कराया जाना। मुख्य रूप से आमजनों को जानकारी दी गयी है। वहीं बताया गया कि जिन धाराओं को समाप्त किया गया है उसमें राजद्रोह, आत्म हत्या का प्रयास, अप्राकृतिक रूप से संभोग करना, ठग, ठग हेतु दंड, व्यभिचार शामिल है। वहीं जो नई धाराओं को जोड़ा गया है। उसमें चाइल्ड बालक/बालिका, भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, प्रवचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हुये ..., न्यायालय की अनुज्ञा के बिना प्रकाशन, क्रूरता, अपराध कारित करने के लिये बालक को भाड़े पर लेना, निन्योजित व नियुक्त करना, मॉब लिंचिंग सहित अन्य धाराओं में इजाफा हुआ है। इन जानकारियों से आमजन को अवगत कराया गया।

## लेडी नदी पुल पर कीचड़ ही कीचड़, आये दिन फिसलकर गिर रहे वाहन चालक

हरिभूमि न्यूज/सड़मर।

जहां एक ओर लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए जहां तहां सड़कों का निर्माण हो रहा है। मगर वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि पूर्व की बनी हुई सड़क जहां बर्दाहल स्थिति में पहुंचने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी ओर न तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और न ही संबंधित विभाग के अधिकारी। इस बात की संचाई इस समय जनपद पंचायत चांवरपाठा के अंतर्गत ग्राम सड़मर से कौड़िया मार्ग पर देखने मिल रही है। बताया जाता है कि इस मार्ग पर सड़क का निर्माण कुछ समय पहले ही हुआ था और चंद दिनों में टूटना शुरू हो चुकी सड़क अपनी गुणवत्ता की कहानी कहने से नहीं चूक रही है। इतना ही नहीं इस मार्ग पर ग्राम महगंवा व



चिरिया के बीच पड़ने वाली लेडी नदी पुल एवं सड़क मार्ग पर कीचड़ ही कीचड़ होने के कारण यहां से

आने जाने वाले दो पहिया वाहन चालक फिसलकर गिर रहे हैं और घायल हो रहे हैं। इस संबंध में क्षेत्र

के लोगों का कहना है कि इस प्रकार से बर्दाहल हो रही सड़क नदी के पुल पर हो रही कीचड़ के चलते दिन में तो वाहन चालक जैसे जैसे पुल पार करके निकल जाते हैं, लेकिन रात्रिकालीन समय अधिकांश ट्रकनाए होती है, इस मार्ग से प्रतिदिन सड़मर, कौड़िया, सुपारी, देगुंवा, तिगांवा, मंहगवा, नया गांव आदि ग्रामों के लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसके आलवा क्षेत्र के छात्र छात्राओं द्वारा भी कौड़िया या गाइरवारा शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसी मार्ग से आना जाना करते हैं जिनको यहां की नदी के पुल पर फैले हुए कीचड़ के साम्राज्य के चलते परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? अतः क्षेत्र के लोगों द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से सड़क सुधार के साथ साथ पुल की मिट्टी हटवाये जाने की मांग की गई है।

## बिना नम्बर के चल रहे सैफेडों टैक्टर, दुर्घटना की बनी आशंका

हरिभूमि न्यूज/नांदेनर/गाइरवारा। जहां एक ओर प्रशासन द्वारा क्षेत्र के अनेक जगहों पर चैकिंग प्वांट लगाकर वाहनों की चैकिंग तो की जा रही है, मगर इसके बाद भी जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा ऐसे वाहनों को नजर अंदाज किया जा रहा है जो वर्षों से बगैर नम्बर प्लेट के दौड़ रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो ट्रेक्टर क्षेत्र में रेत, मरूम का अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है, एक तरफ जहां कभी कभी विभाग द्वारा इस ओर कार्रवाई की जा रही है, वहीं अवैध उत्खनन करने वाले अपने उत्खनन के दौरान अधिकांश रेत कोरोबारी उन ट्रेक्टरों को उपयोग में ला रहे हैं जिनमें नम्बर नहीं लिखा हुआ है, इस प्रकार से बगैर नम्बरों के ट्रेक्टरों से दुलाई कराने के चलते एक तरफ राजस्व को लुप्त करने का नुकसान हो रहा है। वहीं इस पर मजबूर होना पड़ रहा है? अतः क्षेत्र के किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने कारण इन ट्रेक्टर वालों के हासले बुलंद है, क्षेत्र की सड़कों पर इस प्रकार से सैकड़ों ऐसे ट्रेक्टर



बगैर नम्बर चल रहे हैं, जिनमें देखा जावे तो अधिकांश अवैध उत्खनन के कार्य में संलिप्त है? टैक्टरों में जहां एक तरफ बिना नम्बर होने के चलते दुर्घटना के बाद इनकी पहचान करना मुश्किल हो जाती है। वहीं अवैध उत्खनन के समय छापे के दौरान ट्रेक्टर चालकों और मालिकों के भाग जाने से अवैध उत्खनन करने वालों की जानकारी भी आसानी से नहीं मिल पाती है। इस स्थिति में संबंधित विभाग की लापरवाही के चलते जहां क्षेत्र की सड़कों पर इस प्रकार से दौड़ रहे

उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि इस समय यह भी देखा जा रहा है कि ट्रेक्टर चालकों द्वारा रात के समय ट्रेक्टर का उपयोग करते समय सामने का एक ही लाईट चालू किया जाता है जिससे सामने आने वाला व्यक्ति उसे दो पहिया वाहन समझकर साईड देता है और वह दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है। अतः शासन प्रशासन से मांग की जाती है कि बगैर नम्बर तथा एक लाईट व बगैर लाईट के ट्रेक्टरों के खिलाफ एक मुहिम के तहत कार्यवाही की जावे।

## खबर संक्षेप

## मंदिर, आश्रम में संदिग्ध अवस्था में मृत मिला बालक

डिंडोरी। कोतवाली थाना अन्तर्गत जोगीटिकरिया में गोरखनाथ राधा कृष्ण मंदिर आश्रम में रविवार शाम लगभग 5.30 बजे मृत अवस्था में 7वीं कक्षा का छात्र मिला। जानकारी लगते ही ईलाके में सनसनी फैल गई। आश्रम के संचालक सूरज नाथ पिता लक्ष्मी प्रसाद यादव उम्र 40 साल निवासी सुबखार रैयत थाना डिंडोरी ने पुलिस को दिये कथन में बतलाया कि मेरे छोटे भाई सतीष यादव का लडका जो रिश्ते में मेरा भतीजा है गोविन्द यादव उम्र 14 साल मेरे साथ रहकर माध्यमिक शाला जोगीटिकरिया में 7वीं कक्षा को पढ़ाई कर रहा है। रविवार को दिन में करीब 12.30 बजे मैं

जोगीटिकरिया निवासी बिहारी नाथ के यहां गया था आश्रम में भतीजा गोविन्द यादव अकेला था। शाम लगभग 5.30 बजे जब मैं वापस आश्रम आया तो देखा कि रसोई में जहां मैं सोता हूँ वहां पर भतीजा गोविन्द चित्त अवस्था में पड़ा था आवाज देने पर नहीं उठा तब मैं गोविन्द को हाथ से हिलाया और नब्ज देखा तो कुछ समझ नहीं आया तब भोला यादव एवं संजू झारिया के साथ एक कार में तुरंत जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचा जहां चिकित्सको ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। जिसकी सूचना कोतवाली में दी गई, पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए शव का पीएम करा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस ने घटना के संबंध में सभी पहलुओं में जांच शुरू कर दी है।

## शासकीय कार्य में लापरवाही करने पर पटवारी को नोटिस जारी

डिंडोरी। उमेश कुमार जैन पिता खेमचंद जैन निवासी डिंडोरी तहसील व जिला डिंडोरी द्वारा खसरा नंबर 463 जो शासकीय आबादी भूमि पर है। बिना किसी सक्षम अनुमति एवं दस्तावेज के बहुमंजिला इमारत निर्माण किया जा रहा है। जो कि अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है।

मकान मालिक को 05 जुलाई के पूर्व मय दस्तावेज के अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। साथ ही साथ संबंधित क्षेत्र के पटवारी भगवत प्रसाद साहू हल्का पटवारी डिंडोरी के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में लापरवाही किंतु आप के द्वारा आज दिनांक तक उक्त निर्माण के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जो सिविल सेवा आचरण का नियम का उल्लंघन करने पर अनुविभागीय अधिकारी डिंडोरी के द्वारा पटवारी एवं मकान मालिक को नोटिस जारी किया गया।

## आज से होगी सहायक जेल अधीक्षक एवं जेल प्रहरी मर्ती की परीक्षा

अनूपपुर। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा सहायक जेल अधीक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा 25 मई 2023 से 20 जून 2023 तक आयोजित की गई थी। इसका परीक्षा परिणाम 14 मार्च 2024 को घोषित किया जा चुका है। सहायक जेल अधीक्षक एवं जेल प्रहरी के पदों के सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट द्वितीय चरण की परीक्षा जेल विभाग द्वारा स्वयं चलाया जाएगा। प्रथम चरण में चयनित उम्मीदवारों का शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम भोपाल में 2 जुलाई 2024 से 7 जुलाई 2024 तक प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से आयोजित किया जाएगा। सफल अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्रों को निकालकर नियत तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों एवं जानकारी सहित शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट के लिए उपस्थित हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि सहायक जेल अधीक्षक के 33 पद एवं जेल प्रहरी के 200 पदों के लिए मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा क्रमशः 414 एवं 2264 अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण हेतु पात्र पाया गया है, जिनका द्वितीय चरण में शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट दे लिया जाना है। शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल अंतिम चयन सूची जारी करेगा, जिन्हें जेल विभाग द्वारा प्रहरी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

## निर्माणाधीन दो मंजिला पक्का मकान हुआ धरासायी

## मलबे के नीचे दबने से तीन मजदूर घायल, एक की मौत



## रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला गया

डिंडोरी

जिले में विगत दो दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है लगातार बारिश होने के कारण गाडासरई थाना अन्तर्गत करबेमट्टा में सोमवार सुबह लगभग 5 बजे एक दो मंजिला मकान ढह गया जिसमें रह रहे चार मजदूर मलबे के नीचे दब गये। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गाडासरई पुलिस ने ग्रामीणों को मदद से रेस्क्यू कर सभी मजदूरों को बाहर

निकाला जिसमें एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई। वहीं तीन घायल मजदूरों को स्वास्थ्य केन्द्र गाडासरई में लाकर भर्ती कराया गया जहां एक की हालत गंभीर होने से प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक के शव को पंचनामा की कार्यवाई के बाद पीएम के लिए रवाना कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक करबेमट्टा में एक निर्माणाधीन मकान में मोरध्वज पिता हेमसिंह मरावी उम्र 28 वर्ष निवासी धवाडोंगरी, यशवंतसिंह पिता दलसिंह नेताम उम्र 23 साल निवासी धवाडोंगरी, जागेश्वर पिता भोगसिंह उम्र 32 साल धवाडोंगरी, एवं शंकर बंजारा पिता जगदीश बंजारा उम्र 30 साल निवासी धवाडोंगरी पिछले चार माह से रह रहे थे और इस मकान के अलावा अन्य मकान निर्माण में मजदूरी का कार्य करते थे। रविवार को सभी मजदूर भोजन करने के बाद सो गये थे। सोमवार सुबह लगभग 5 बजे अचानक मकान भरभरा कर गिर गया जिसके मलबा के नीचे चारो मजदूर दब गये। पड़ोसियों ने मकान गिरने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे और पुलिस को इस बावद सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचे ग्रामीणों को मदद से रेस्क्यू शुरू किया।

## नया कानून जागरूकता जन संवाद कार्यक्रम



डिंडोरी। आज दिनांक 01.07.2024 से सम्पूर्ण भारत में लागू होने वाले नये कानून भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय डिंडोरी (म.प्र.) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

महोदय डिंडोरी एवं उप पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना परिसर समनापुर में जन संवाद एवं जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया जिसमें थाना क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि गण, जनपद सीईओ, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर व शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय

समनापुर के प्राचार्य, शिक्षकगण, स्कूली बच्चे, ग्राम रक्षा समिति सदस्य, ग्राम कोटवार, वन विभाग, पंचायत विभाग, डाक विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, जनपद पंचायत प्रतिनिधिगण, विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच-सचिव, पत्रकार गण एवं थाना स्टाफ

सहित लगभग 250 लोग उपस्थित हुए जिन्हे थाना प्रभारी समनापुर, जनपद सीईओ, प्राचार्य एवं वन प्रतिनिधियों के द्वारा नये कानूनों के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिनिधिगण, विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच-सचिव, पत्रकार गण द्वारा थाना परिसर में वृक्षारोपण किया गया।

## बजाग थाना परिसर में संपन्न हुई बी एन एस हेतु बैठक

डिंडोरी। थाना परिसर बजाग में पूरे देश में कानून न्याय संहिता लागू हो गई है जिसमें अनेक धाराओं के नंबर बदले गए हैं जिनमें अनेक कानून न ए तथा अनेक कानूनों को समाप्त किया गया है। इसी तारतम्य में थाना परिसर बजाग में एक बैठक हुई जिसमें विभागीय अधिकारी एस डी ओ पी, टी आई बी पंडेरिया, एस आई अशोक तिवारी, अजय पाल डिप्टी रेंजर, डाक्टर विपिन सिंह, शंकर धुवे सरपंच बजाग रैयत, द्रोपदी रौतेल सरपंच बजाग माल, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश्वर साहू, वरिष्ठ भाजपा नेता कमलेश पट्टेयरी, धर्मेश पाल मानिकपुरी ओबीसी मोर्चा जिला संयोजक, प्रमोद साहू, चूराम साहू, मुरारी साहू, नीरज मुजवार, यशवंत साहू सहित अनेक गणमान्य एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे।



## शासकीय महाविद्यालय करंजिया मे मनाया गया दीक्षारंभ समारोह

करंजिया। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 1 जुलाई को शासकीय महाविद्यालय करंजिया में नव प्रवेशित विद्यार्थियों को नए परिवेश में सहज महसूस कराने, उनमें संस्थान की विशिष्ट प्रकृति तथा संस्कृति को सिखाने, अन्य छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ संबंध बनाने तथा उन्हें व्यापक उद्देश्य तथा स्वयं की खोज की भावना से परिचित कराने के उद्देश्य से दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षारंभ कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य प्रमोद कुमार वासने ने मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। तब उपरान्त महाविद्यालय के प्रो. अजय सिंह ने दीक्षारंभ समारोह की रूप रेखा को विस्तार से उपस्थित विद्यार्थियों के मध्य अपने विचार रखे जिसमें संकाय मार्गदर्शक, एनसीसी, एनएसएस, शासन की महाविद्यालय में संचालित विभिन्न योजनाएं आदि पर विस्तार से चर्चा की गई।

## कला, संस्कृति के साथ व्याख्यान भी होंगे

तीन दिनों तक आयोजित होने वाले दीक्षारंभ कार्यक्रम का उद्देश्य नए विद्यार्थियों को नए परिवेश में सहज महसूस कराने, उनमें संस्थान की विशिष्ट प्रकृति तथा संस्कृति को सिखाने के प्रयास होंगे। समारोह के दौरान कई तरह की गतिविधियां होंगी। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस दौरान विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। साथ ही इसमें शारीरिक क्रियाकलाप, मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सृजनात्मक कला तथा संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम होंगे। इस दौरान विद्यार्थियों की आकांक्षाओं का समाधान किया जा रहा है।

## ग्रामीण अंचलों में छाया अंधेरा, अंधेरे में हो रही घटनाएं, जहरीले जीव जंतुओं का बढ़ा खतरा

डिंडोरी। बरसात के शुरू होते ही जहरीले जीव जंतु अपने बिलों से बाहर निकलकर बाहर खुले वातावरण में विचरण करने लगते हैं तथा बरसात में घरों में भी घुस जाते हैं और यही जहरीले जंतु खतरा महसूस होने पर मनुष्यों और जानवरों को काट लेते हैं जिससे उनके विष से जान तक जा सकती है ऐसा ही एक घटना बजाग थानांतर्गत ग्राम सारंगपुर के भड़भड़ो टोला में घटित हुई है जहा एक छह साल के मासूम को सोते हुए जहरीले सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा तैयार कर मर्ग कायम करते हुए मृत बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जिसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। उक्त घटना के बाद ग्राम के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर नाराजगी जताते हुए इस घटना के लिए

विभाग को जिम्मेदार ठहराया। और कहा की घटना के समय पूरा परिवार लाइट नहीं होने के कारण रात के अंधेरे में जमीन पर सोया हुआ था उसी वक्त मासूम बच्चे को सर्प ने काट लिया और बच्चे की असमय जान चली गई। लगभग दो माह से ग्राम के आवास टोला में बिजली आपूर्ति बाधित होने की जानकारी भी सामने आई है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक सारंगपुर आवास टोला के भड़भड़ो टोला में रवि किसन पिता भानसिंह धुवे उम्र आठ वर्ष अपने घर में परिवार के साथ जमीन पर सो रहा था तभी सुबह चार बजे के लगभग अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर परिजन उठ गए और देखा की बच्चे को सर्प ने काट लिया है गांव में तत्काल कोई साधन उपलब्ध नहीं होने के चलते परिजन बच्चे को इलाज के लिए समय पर

कही नहीं ले जा पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी और लगभग दो घंटे के बाद सुबह छह बजे बच्चे ने दम तोड़ दिया। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही है इस घटना से लचर विद्युत व्यवस्था के प्रति लोगो की नाराजगी देखी गई। बजाग आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्र है यहां से कुछ दूरी पर बसे आसपास के ग्राम घने वनों से घिरे हुए हैं शाम होते आदिवासी अंचलों में घुप अंधेरा हो जाता है मैदानो और खेतों में जहरीले जीव जंतुओं के अलावा वन्यजीवो का खतरा हर समय बना रहता है ऐसे में बिजली का उजाला ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ा सहायक होता है परंतु बिजली विभाग की घोर लापरवाही से लोगो को अंधेरे में समय व्यतीत करना पड़ रहा है और सर्पदंस जैसी घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है।

## "एक पेड़ मां के नाम" अभियान से जुड़े प्रत्येक प्रदेशवासी

डिंडोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "एक पेड़ मां के नाम" अभियान चलाया है। मध्यप्रदेश सरकार भी पर्यावरण के प्रति गंभीर है। लगभग साढ़े 5 करोड़ पौधे मध्यप्रदेश में लगायेंगे। ऐसा प्रयास है कि प्रदेश में 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच अलग-अलग जिलों में इस अभियान को चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक टीवी संदेश के माध्यम से कहा कि मुझे संतोष है कि कई जिले जैसे डिंडोरी में लगभग 5 लाख पौधे लगाने वाला है। जिसमें वन विभाग, आईडब्ल्यूएमपी, मध्यप्रदेश आजीविका मिशन एवं समस्त विभागों के द्वारा पौधारोपण किए जायेंगे। पौधारोपण के लिए शारदा टेकरी डिंडोरी में स्मृति वन, कन्या शिक्षा परिसर, विद्यालय परिसर, आंगनवाड़ी, शारदा टेकरी शहपुरा, नर्मदा नदी के किनारे झूब क्षेत्र के बाहर एवं पीएम जनमन के सात आदर्श ग्राम, मंगल ग्राम एवं सभी विभागों में संचालित स्थलों को चिह्नित किया गया है। पौधारोपण हेतु आम, अमरूद, नीम, पीपल, कटहल, जामुन, करंज, मुनगा, शीशम तथा शहतुत पौधों को शामिल किया गया है। ऐसे कार्यों से ही पर्यावरण का माहौल बनता है।



ऐसे में पौधारोपण कर न केवल हम पर्यावरण को बचाएंगे बल्कि वानिकीकरण में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस पूरे आयोजन के प्रति सरकार गंभीर है, यह अभियान लगातार चलता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आप सभी को इस अभियान से जुड़ने की अपील करता हूँ। आप अपने परिजन को लेकर, माता जी को साथ लेकर सेल्फी लें। अगर माता जी नहीं है तो उनके चित्र के साथ एक पौधा लगाकर सेल्फी ले सकते हैं। अभियान के अंतर्गत निर्धारित वेबसाइट पर भी चित्र अपलोड किया जा सकता है। इससे अन्य लोग प्रेरित होंगे। शासन प्रशासन द्वारा बताए गए निर्धारित स्थान पर पौधे लगाए, सरकार उनकी देखभाल करेगी।

## मंत्री विश्वास सारंग को हटाने कांग्रेस ने सौपा ज्ञापन

डिंडोरी। जिला कांग्रेस के द्वारा मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम डिंडोरी नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौपा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक पडवार का आरोप है की मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें अस्तित्वहीन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता एवं नर्सिंग कॉलेज से संबंधित छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने की घटना विस्तृत रूप से उजागर हुई है जिसमें मध्यप्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटक रहा है। उक्त नर्सिंग घोटाले में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यकाल की घटनाएं उजागर हुई है जिसके लिए मंत्री सारंग सीधे सीधे जिम्मेदार है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री

विश्वास सारंग आज भी अपने पद पर काबिज है। उपरोक्त नर्सिंग कॉलेज घोटाला छात्र-छात्राओं के भविष्य के अंधकारमय करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुख्य अवर सचिव मोहम्मद सुलेमान, तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत बरबडे सहित कई अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों की संलिप्तता उजागर हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों सहित आम जनता में भारी रोष व्याप्त है। अतः महामहिम आपसे निवेदन है कि प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले जैसे कलंक की सम्पूर्ण जांच कराकर कार्यवाही की जावे एवं जांच पूर्ण होने के पूर्ण प्रथम दृष्टा अपराध में संलिप्त प्रतीत हो रहे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास



सारंग, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान एवं निशांत बरबडे को तत्काल निलंबित कर जांच कार्यवाही कराई जावे एवं मंत्री विश्वास सारंग को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जावे जो न्यायचित्त होगा। ज्ञापन सौपने पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक पडवार, महेंद्र ठाकुर, तोकसिंह मरावी, सिंग्राम धुवे, संतोष सारंग, शिवकुमार, देवसिंह भारतीय, विष्णुनाथ कुशराम, मकसूद मंसूरी, एवं खालिद सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे।

